UNIVERSITY NEWS 08 MARCH 2026

AMAR UJALA

लविवि : कुलपति से मिले पूर्व छात्र

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय पुरातन छात्र संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी से मुलाकात की। विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व महामंत्री अनिल सिंह वीरू, ज्ञानेंद्र शुक्ला, शरफ अब्बास ने कुलपति से अपने दौर की यादें साझा की। कुलपति ने हबीबुल्लाह छात्रावास की ओर से संपादित पत्रिका युगांतर भी भेंट की। कुलपति ने पुरातन छात्रों और प्रशासन के परस्पर सहयोग से लविवि की गौरवशाली परंपरा को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। (संवाद)

DAINIK JAGRAN

तृतीय वैश्विक विदुषी सम्मेलन में 20 महिलाएं सम्मानित

सम्मेलन में बीएयू के संस्कृत विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. मनु लता शर्मा, कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विवि बीकानेर, प्रो. मनोज दीक्षित, माता सुंदरी कालेज दिल्ली की कुलपति, प्रो. हरप्रीत कौर, ग्लोबल संस्कृत फोरम के अध्यक्ष प्रो. हरिदत्त शर्मा • जागरण

जासं • लखनऊ: तृतीय वैश्विक विदुषी सम्मेलन में ग्लोबल संस्कृत फोरम के राष्ट्रीय सचिव डा. राजेश मिश्र व कई प्रदेशों से आईं 20 विदुषी महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान पांच संपादकीय पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान के बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित ने कहा कि भारतीय संस्कृति व मूल्यों की स्थापना में स्त्री का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रो. मनु शर्मा ने कहा कि ऋग्वेद में नववधुओं को गृह प्रवेश के समय ही साम्राज्ञी कहलाती थीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. हरिदत्त शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वनारस से प्रो. रचना दूबे, दिल्ली के माता सुंदरी महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर हरप्रीत कौर आदि उपस्थित रहे।

I NEXT

जेंडर गेप मे आई कमी, वर्कफोर्स में भी वीमेन को आना होगा आगे

एलयू के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने 20 सालों के डेटा के बेस पर की रिसर्च स्टडी

lucknow@inext.co.in

20 साल के डाटा का एनालिसिस

LUCKNOW(7 March): लखनऊ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर डॉ. रोली मिश्रा और रिसर्चर विष्णु कुमार ने साउथ एशिया में पिछले दो दशक में जेंडर गैप और वर्कफोर्स में वीमेंस के कंट्रीब्यूशन को लेकर रिसर्च स्टडी की. यह रिसर्च स्टडी साउथ एशियाज जेंडर डिवाइड स्ट्रक्चरल एंड सोशल बैरियर्स टाइटल से इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल मिलेनियल एशिया में पब्लिश किया गया है, जो सेज पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है और सोशल स्टडीज के फील्ड में क्यू 1 कैटेगरी में शामिल है. प्रो. रोली मिश्रा की स्टडी में निकलकर आया है कि साउथ एशिया में बीते 20 सालों में जेंडर गैप में कमी आई है लेकिन वर्कफोर्स में अभी भी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन कंपेरेटिवली कम है.

प्रोफेसर रोली मिश्रा ने बताया कि इस रिसर्च स्टडी में 2003 से 2022 तक के 20 सालों के दौरान साउथ एशिया के 8 देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव में जेंडर गैप का एनालिसिस किया गया. जिसके लिए हमने जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स नामक एक नया सूचकांक विकसित किया है. जो स्वास्थ्य, शिक्षा और वर्क फोर्स मे मेल-फीमेल के डिफरेंस को मापता है. रिसर्च में सामने आया है कि घरेलू जिम्मेदारियां, वाइल्डकेयर सुविधाओं की कमी और सुरक्षा संबंधी चिंताएं महिलाओं के फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन को सीमित करती है.

योजना से महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार

अध्ययन दक्षिण एशिया में महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक असमानता पिछले दो दशकों मे धीरे-धीरे कम हुई है, लेकिन महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी चुनौती बनी हुई है। भारत में जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने में मदद की है। यह निष्कर्ष एलयू के अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर रोली मिश्रा और शोधार्थी विष्णु कुमार के 'साउथ एशिया जेंडर डिवाइड: स्ट्रक्चरल एंड सोशल बैरियर्स' शीर्षक से प्रकाशित एक अध्ययन में सामने आया है, जो मिलेनियल एशिया 2026 में प्रकाशित हुआ है। यह जर्नल स्कोपस में सूचीबद्ध सेज पब्लिकेशन्स की ओर से प्रकाशित किया जाता है। प्रोफेसर रोली मिश्रा ने बताया कि शोध में 2003 से 2022 तक के 20 वर्षों के दौरान दक्षिण एशिया के आठ देशों का विश्लेषण किया गया है।

HINDUSTAN

महिलाओं ने गाए गीत तो सम्मेलन में हुआ मंथन

- लखनऊ विवि के मालवीय सभागार में विदुषी सम्मेलन हुआ। इंटरनेशनल संस्कृत ग्लोबल फोरम, नवयुग महाविद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महाविद्यालय, नारी शिक्षा निकेतन महाविद्यालय और महिला महाविद्यालय डिग्री कॉलेज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने कहा कि हम पहले कैसे सुदृढ़ थे उस कारण को खोजना होगा।
- सीसीएस एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर एमडी ने शक्ति मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और अधिकारियों के साथ विशेष रूप से डिजाइन इस मेट्रो ट्रेन में सवार होकर 'एवजीविशन ऑन व्हील्स' का अवलोकन किया, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रमुख महिलाओं की प्रेरणादायक यात्राओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। मेट्रो यात्री आवागमन के दौरान इसे देख सकेंगे।
- 'शो योर टैलेंट' पहल के तहत हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर एक संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। एमडी ने कहा कि मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि हमारी हर तीन में से एक ट्रेन महिला ट्रेन ऑपरेटर द्वारा संचालित की जाती है।
- प्रेस क्लब में महिला कानूनों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता विषयक संगोष्ठी हुई।

AMAR UJALA

मूल्यों की स्थापना में नारियों की भूमिका अहम

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में सभी नारी शक्ति अपनी पूर्णकला में स्फुरित विषय पर वैश्विक विदुषी सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने की। उन्होंने कहा कि हम पहले कैसे सुदृढ़ थे उस कारण को खोजना होगा क्योंकि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व हमारी जीडीपी बहुत अच्छी थी। मूल्यों की स्थापना में नारियों की भूमिका अहम है। ग्लोबल संस्कृत फोरम के राष्ट्रीय सचिव डॉ. राजेश मिश्र, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. हरिदत्त शर्मा, प्रो. रचना दुबे ,माता सुंदरी महाविद्यालय दिल्ली की प्राचार्या प्रोफेसर हर प्रीत कौर, नेता जी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर रश्मि विश्नोई विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज की प्राचार्या प्रो. धर्म कौर मौजूद रहीं। (संवाद)

डॉ. भावना मिश्रा : लविवि की पहली महिला कुलसचिव

लखनऊ विवि के 105 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महिला को कुलसचिव बनाया गया और यह जिम्मेदारी डॉ. भावना मिश्रा निभा रही हैं। इससे पहले वह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक और कुलसचिव के पद पर कार्य कर चुकी हैं। प्रशासनिक अनुभव और शैक्षणिक समझ के साथ वह विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में जुटी हैं।

NBT

एलयू का अध्ययन: 'लैंगिक समानता में देश भूटान और श्रीलंका से भी पीछे'

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ:** लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की ओर से किए गए एक अध्ययन मे सामने आई कि जेंडर गैप कम करने के मामले मे भारत, मालदीव, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों से भी पिछड़ा हुआ है। एलयू के इकॉनमिक्स विभाग की ओर से पिछले बीस सालों के आकड़ों के अध्ययन के आधार पर यह स्टडी की गई है जिसे 'मिलेनियल एशिया' जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इकॉनमिक्स विभाग की प्रो. रोली मिश्रा और विष्णु कुमार ने यह अध्ययन किया है। प्रो. रोली मिश्रा ने बताया कि हमने वर्ल्ड बैंक के जेंडर पोर्टल से डेटा साल 2003 से 2022 तक का डेटा जुटाया। इस अध्ययन मे दक्षिण एशिया के आठ देशों-भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव मे स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम बाजार मे महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण किया गया। अध्ययन मे यह भी रेखांकित किया गया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार के बावजूद, महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी भारत सहित पूरे दक्षिण एशिय के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

HINDUSTAN TIMES

SCHOLARS' CONFERENCE ON 'SHAKTI' AT LU

LUCKNOW: On the eve of International Women's Day, the third Global Scholars' Conference was organised at Lucknow University on Saturday. The event took place at the Malviya Auditorium and was organised by the department of Sanskrit and Prakrit Languages of the university along with the Global Sanskrit Forum, Navyug Kanya Mahavidyalaya, Netaji Subhash Chandra Bose Government College, Nari Niketan Mahavidyalaya and Mahila Mahavidyalaya Degree College on the theme "Shakti in its full glory."

LU study: South Asia shows progress, but long-term policy commitment required

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW: A recent study by the economics department of Lucknow University found that gender inequality in South Asia gradually decreased between 2003 and 2022. Improvements in health services—such as improved maternity health services, increased life expectancy, and reduced child mortality—have played a significant role in reducing this gap.

Despite improvements in health and education, the study highlights that women's labour market participation remains a major challenge in South Asia.

Social perceptions that domestic work and caregiving are primarily women's responsibility, lack of adequate childcare facilities, and safety concerns limit women's economic participation. LU faculty member Prof Roli Misra said increasing women's participation in the workforce is essential not only for gender equality but also for economic development and inclusive growth. "The study recommends that governments should take strong policy measures to reduce gender inequality, including increasing girls' access to secondary and higher education, strengthening health infrastructure, creating secure and flexible employment opportunities for women, and investing in childcare and social infrastructure," Misra said.

The study analysed gender disparities in eight South Asian countries: India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, and the Maldives.

"In order to understand these differences, we developed a new index called the Gender Disparity Index (GDI), which measures the gap between men and women in three key areas: health, education, and labour market participation. This type of region-specific index focused on South Asia has not been developed before, making this study an important contribution to research on gender inequality in the region," said Misra.

Out of eight countries analysed, Maldives, Bhutan, and Sri Lanka emerged the best performers in reducing gender inequality. They have consistently invested in health and education, expanding opportunities for women and leading to better development outcomes.

India, Bangladesh, and Nepal fall into the middle category of the index, showing some improvement in the gender gap.

"In India, government initiatives such as the Janani Suraksha Yojana, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Pradhan Mantri Matra Vandana Yojana, and various skill development programmes have contributed to improving women's health and education. The Gender Inclusion Fund launched under the National Education Policy 2020 is an important step towards ensuring equal opportunities in education," said Misra.

The authors also emphasise the importance of gender-responsive budgeting to ensure that government spending promotes women's socio-economic empowerment.